UPSC-CSE 2027/28
DAILY
CURRENT AFFAIRS
ONE STOP SOLUTION
By Faiyaz Sir
The Indian EXPRESS
THE HINDU
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
26 AUGUST
COMPQETE COVERAGE
EXAM FOCUSED
ANALYSIS MADE EASY
STATIC + CURRENT INTEGRATION
STAY AHEAD STAY PREPARED

Result Mitra

“हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं,
अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखें।”

Walt Disney

वॉल्ट डिज़नी

ResultMitra

आज क्या पढ़ेंगे?

1. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)
2. महत्वपूर्ण तथ्य

Geography
Economics
P.I

Result Mitra

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाया

उपाध्यक्ष एस. मुनावरी बेगम ने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं तथा शांति, करुणा एवं राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर प्रकाश डाला

प्रविष्टि तिथि: 25 AUG 2026 6:56PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनएमसी) ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्य एवं आयोग के अधिकारी पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए और उनके जीवन, शिक्षाओं एवं शांति, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी के सतत संदेश पर विचार किया।

Result Mitra

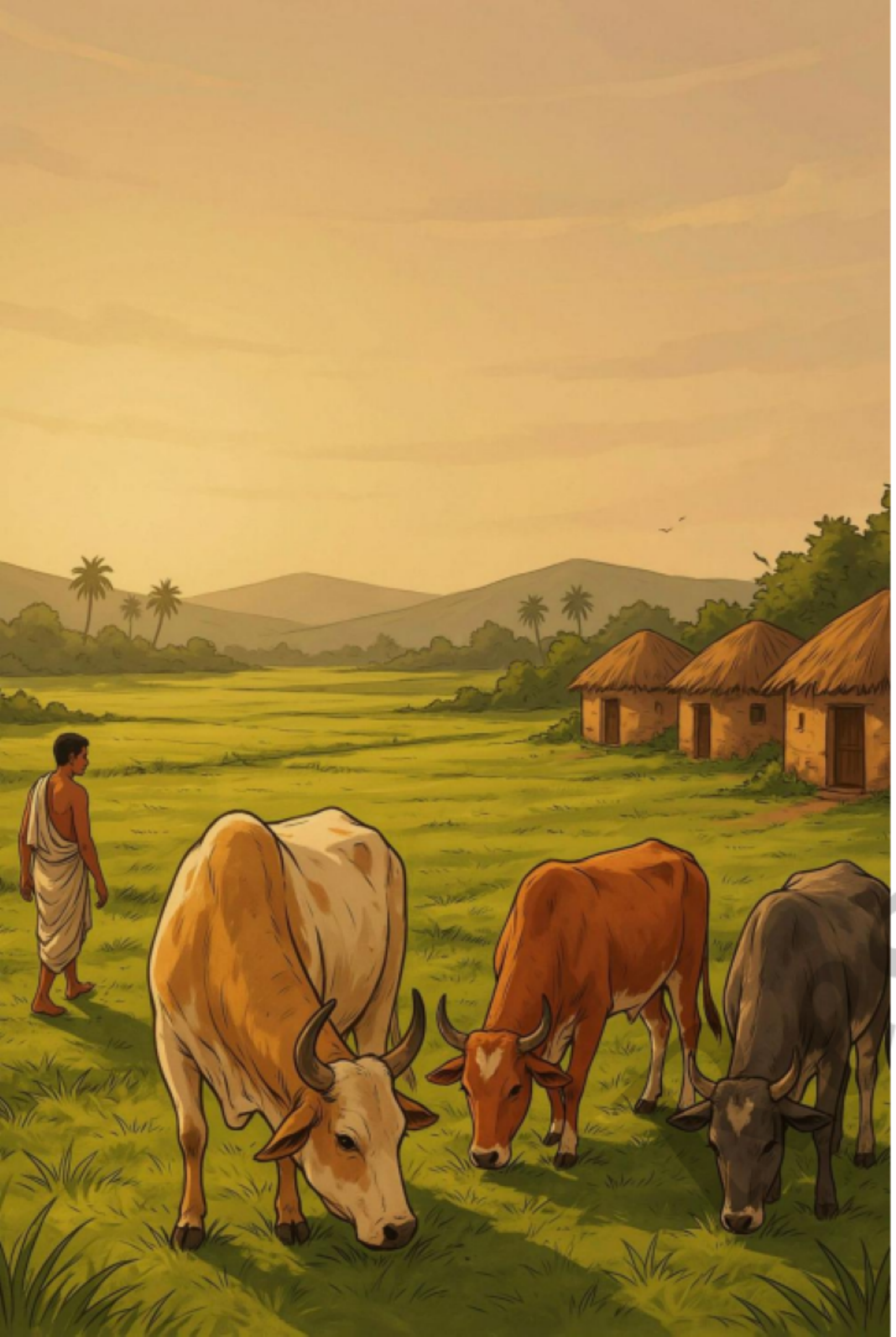

भारत सरकार
पत्र सूचना कार्यालय

Farmer's Welfare

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)

'भारतीय पशुधन के लिए रोग मुक्त भविष्य'

Posted On: 22 AUG 2026 10:14AM

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई। यह भारत के सबसे बड़े पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य देशव्यापी टीकाकरण और निगरानी के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) तथा ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण और इनका उन्मूलन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एफएमडी के **147.16 करोड़** टीके लगाए गए जिसका लाभ **8.04 करोड़** किसानों को मिला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि से रोगों के मामले घटाने में काफी मदद मिली है। 2019 में एफएमडी के **132** मामले सामने आए थे जिनकी संख्या 2025 में घट कर **40** हो गई। इसी तरह, ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 में 22 से घट कर 2025 में **15** हो गए। एनएसपी एंटीबॉडी की मौजूदगी भी 2019 में 20.8 प्रतिशत से घट कर 2025 में 8.1 प्रतिशत रह गई है। इससे साक्ष्य आधारित निगरानी और रोग नियंत्रण की निरंतर कोशिशों के परिणामस्वरूप एफएमडी के प्रसार में कमी आने का संकेत मिलता है। देश में पिछले 3 वर्षों में सीरोटाइप एशिया-1 से उत्पन्न एफएमडी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस कार्यक्रम को मजबूत पशु चिकित्सा अवसंरचना, पशुधन के बारे में डिजिटल आंकड़ों, अनुसंधान संस्थानों और वन हेल्थ पहलकदमियों से सहायता मिली है। भारत पशुधन पोर्टल पर **39.00 करोड़** से अधिक मवेशी पंजीकृत हैं। **4019 सचल** पशु चिकित्सा इकाइयों ने **136 लाख किसानों** को उनके घर पर सेवा मुहैया कराते हुए **276 लाख मवेशियों** का इलाज किया है। एनएडीसीपी रोग नियंत्रण, डिजिटल निगरानी और महामारी की तैयारी को समेकित करते हुए भारत में रोगों से सुरक्षित पशुधन क्षेत्र में योगदान कर रहा है।

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और आजीविका की रीढ़ माना जाने वाला पशुधन क्षेत्र देश के कृषि विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और डेयरी उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2019 में 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (NADCP) की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम देश के सबसे बड़े पशुधन स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जो 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

Result Mitra

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और वित्तीय परिव्यय

शुरुआत और मुख्य उद्देश्य

सितंबर 2019 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशव्यापी टीकाकरण और मजबूत निगरानी के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) तथा ब्रूसेलोसिस (Brucellosis) पर पूर्ण नियंत्रण पाना और उनका उन्मूलन करना है।

बजट परिव्यय

पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधित 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (LHDCP) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹2,010 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है।

Result Mitra

लक्षित बीमारियाँ और वैज्ञानिक टीकाकरण रणनीतियाँ

खुरपका और मुंहपका रोग (Foot and Mouth Disease)

यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं का अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जिससे दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता गिरती है। इसके नियंत्रण के लिए सभी संवेदनशील पशुओं का वर्ष में दो बार 100% सामूहिक टीकाकरण किया जाता है। वर्ष 2024 से इसमें घुमंतू चरवाहों के पशुओं (जैसे भेड़-बकरी) को भी शामिल किया गया है।

ब्रूसेलोसिस (Brucellosis)

यह 'ब्रूसेला एबॉर्टस' बैक्टीरिया के कारण होने वाला गोवंशीय मवेशियों (गायों और भैंसों) का प्रजनन संबंधी गंभीर रोग है, जिसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके बचाव हेतु 4 से 8 महीने की बछियों को जीवनकाल में एक बार टीका लगाया जाता है।

Result Mitra

कार्यक्रम के मापने योग्य परिणाम और प्रभाव

147.16 Cr

टीके लगाए गए

FMD के तहत अब तक 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिससे 8.04 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।

40

FMD मामले 2025 में

FMD के मामले 2019 के 132 से घटकर 2025 में मात्र 40 रह गए हैं। पिछले 3 वर्षों से 'सीरोटाइप एशिया-1' का कोई मामला सामने नहीं आया है।

15

ब्रूसेलोसिस मामले 2025

ब्रूसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं।

36.63%

उत्पादकता वृद्धि

भारत में गोवंशीय मवेशियों की औसत उत्पादकता 2014-15 के 1,640 किग्रा से बढ़कर 2024-25 में 2,250 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है।

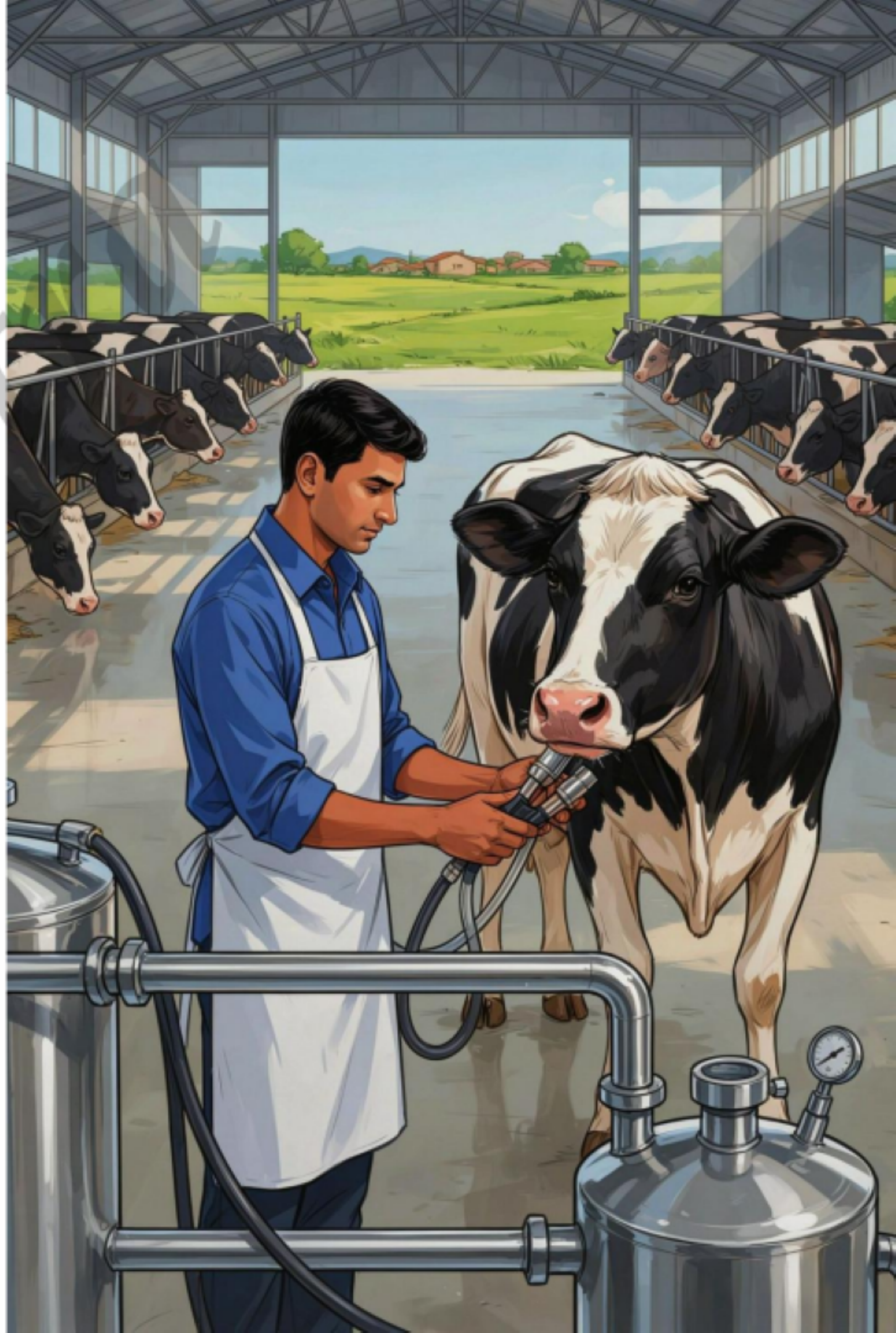

Result Mitra

दुग्ध उत्पादन और डिजिटल एकीकरण

देश का कुल दूध उत्पादन 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया है (69.4% की वृद्धि)। लक्ष्य 2030 तक प्रति जानवर 3,000 किग्रा औसत उत्पादन हासिल करना है।

भारत पशुधन पोर्टल

प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी से जोड़ा गया है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39.00 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिससे वास्तविक समय (Real-time) निगरानी संभव हुई है।

सचल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVUs)

29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,019 MVUs टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं, जिससे 136 लाख किसानों को लाभ और 276 लाख पशुओं का इलाज मिला है।

Result Mitra

MAITRI कार्यक्रम और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण

MAITRI कार्यक्रम

ग्रामीण स्तर पर पशु स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर पहुँचाने के लिए 39,810 बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है।

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण और महामारी कोष

मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए ज़ूनोटिक रोगों के प्रसार को रोकना तथा G20 महामारी कोष के सहयोग से प्रयोगशालाओं व जीनोमिक निगरानी को मजबूत करना।

Result Mit

'वन हेल्थ' दृष्टिकोण और महामारी की तैयारी

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन

मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को समझते हुए यह मिशन ज़ूनोटिक रोगों (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों) के प्रसार को रोकने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को नियंत्रित करने पर जोर देता है।

महामारी कोष परियोजना

2024 में जी20 महामारी कोष, एशियाई विकास बैंक, FAO और विश्व बैंक के सहयोग से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू की गई है, जो प्रयोगशालाओं और जीनोमिक निगरानी को उन्नत करती है।

महत्वपूर्ण मार्गदर्शिकाएँ

सरकार ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (SVTG) और पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (CMP) जारी की है, जो संकट के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।

Result Mitra

प्रमुख चुनौतियाँ

संक्रामक रोगों का उच्च जोखिम

FMD और ब्रूसेलोसिस जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलकर पशुओं की उत्पादकता और प्रजनन क्षमता को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं।

घुमंतु और प्रवासी पशुओं की निगरानी

पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों में चरवाहों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाले पशुओं के झुंडों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है।

कोल्ड-चेन और लॉजिस्टिक्स की सीमाएँ

दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में टीकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक शीत श्रृंखला का रखरखाव करना चुनौतीपूर्ण होता है।

Result Mitra

किसानों में जागरूकता का अभाव और समाधान

कई बार ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक समय पर टीकाकरण और कान टैगिंग के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं।

समाधान और उपचारात्मक उपाय:

नियमित सामूहिक टीकाकरण

FMD के लिए वर्ष में दो बार 100% टीकाकरण तथा ब्रूसेलोसिस के लिए 4 से 8 माह की बछियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।

विशेष प्रवासी अभियान

वर्ष 2024 से चरवाहों के पशुओं (भेड़-बकरी) के लिए भी विशेष FMD टीकाकरण अभियान का संचालन करना।

डिजिटल ट्रैकिंग और MVUs

'भारत पशुधन पोर्टल' के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड रखना तथा 1962 हेल्पलाइन के जरिए घर-घर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।

Result Mitra

क्षमता निर्माण एवं वन हेल्थ पहल और निष्कर्ष

MAITRI कार्यक्रम के तहत तकनीशियनों का प्रशिक्षण और 'वन हेल्थ मिशन' के माध्यम से संक्रामक रोगों के प्रसार पर रोक लगाना।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) ने उत्कृष्ट टीकाकरण कवरेज, उन्नत डिजिटल नेटवर्क और मजबूत बुनियादी ढांचे के बल पर भारतीय पशुधन संपदा को एक नया सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह पहल किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

sult Mitra

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशव्यापी टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) तथा ब्रूसेलोसिस पर नियंत्रण और उनका उन्मूलन करना है।
2. ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण हेतु 4 से 8 महीने की बछियों का उनके जीवनकाल में एक बार टीकाकरण किया जाता है।
3. वर्ष 2024 से इसमें घुमंतू चरवाहों की भेड़ों और बकरियों के लिए भी FMD टीकाकरण शुरू किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Result Mitra

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Answer writing

check

प्रश्न: 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (NADCP) किस प्रकार भारत के पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किसानों की आजीविका और 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सहायक है? विस्तार से चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

15 अंक

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

SC mulls special Bench on OBC creamy-layer issue

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday agreed to consider setting up a special Bench to hear the Centre's plea seeking clarification on the applicability of its March 11 judgment on creamy-layer criteria for Other Backward Class (OBC) candidates of the civil services examination held in 2025.

The Department of Personnel and Training (DoPT) wants the court to let it proceed with service allocation of the 958 candidates recommended by the Union Public Service Commission on the basis of the wealth/income test criteria applied before the March 11 verdict in *Union of India v. Rohith Nathan*.

Retrospective implementation will be "extremely difficult" and will cause a "cascading effect" on settled service matters from 2012, which will extend its impact to "all categories, including the Unreserved category", the Centre told the court.

The March 11 ruling had directed the Centre to create supernumerary posts for OBC candidates who had been excluded from reservation benefits on the ground that they fell within the creamy layer solely because of their parents' salaries.

The DoPT warned that this could trigger a barrage of claims or contestations from candidates denied OBC non-creamy layer status, as well as from those who did not seek such certification at the time of recruitment, examination, or admission, but may now seek to rely on the judgment. It would also "drastically" alter the seniority landscape, the DoPT said.

The govt. has sought clarification on a March 11 judgment by the top court on the OBC criteria.

The Supreme Court's March 11 judgment laid down the law on how to interpret the income/wealth test component of the government's creamy layer exclusion framework for OBCs, for the purposes of reservations in public education and employment.

The court noted that the income test was being applied in a way that was creating "hostile discrimination" between the children of those in government service and those in private employment. In the absence of an established equivalence between the relevant posts, the income test was being applied to rule out OBC candidates whose parents are employed outside government service, while OBC candidates whose parents are government servants were being subjected to a test that did not include parental salary component.

In the applications, the Centre asked to proceed with the CSE 2025 based on the erstwhile interpretation, since the foundation course for this batch is set to start at the end of this month, and it would be unfair to the applicants who applied with the erstwhile understanding of the income test.

Implementation of the SC decision "may adversely affect the spirit and intention of the reservation policy", the Centre argued, saying that the income test becomes the "sole intelligible differentia of economic status and access to resources" when it comes to comparing OBC candidates with "limited access to resources" and OBC candidates with "economically well-off parents earning higher salary income in private sector".

"The direction to create supernumerary posts addresses only the numerical problem of accommodation; it does not resolve these collateral consequences for seniority, promotion and cadre placement," the DoPT said.

YouTube Homework

- Reservation

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा **11 मार्च 2026** को OBC क्रीमी लेयर (Creamy Layer) पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस पर दिए गए जवाब/दाखिल की गई याचिका का विवरण नीचे दिया गया है:

11 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने **'रोहित नाथन'** मामले में फैसला सुनाते हुए OBC क्रीमी लेयर निर्धारण के नियमों को स्पष्ट किया:
- **केवल 'वेतन/आय' आधार नहीं हो सकता:** कोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार का क्रीमी लेयर स्टेटस **केवल उसके माता-पिता की वेतन/आय (Income)** के आधार पर तय नहीं किया जा सकता।
- **पद/रैंक (Status) प्राथमिकता है:** क्रीमी लेयर तय करने का प्राथमिक आधार माता-पिता का **पद (Group A, B, C, D) और उनका सामाजिक स्टेटस** है।
- **सरकारी बनाम निजी/PSU कर्मचारियों में भेदभाव खत्म:** कोर्ट ने DoPT के 2004 के उस स्पष्टीकरण (Clarification) को खारिज कर दिया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को राहत मिलती थी, लेकिन PSU और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी 8 लाख से ज्यादा होने पर उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में डालकर OBC आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन माना।
- **प्रभावित उम्मीदवारों को राहत:** सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2016 के बाद से सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) में इस गलत नियम के कारण बाहर किए गए लगभग 100 उम्मीदवारों के दावों पर विचार किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर **सुपरन्यूमेरेरी (Supernumerary) पद** सृजित कर उन्हें सेवा में शामिल किया जाए। इसके क्रियान्वयन के लिए 6 महीने (11 सितंबर 2026 तक) का समय दिया गया था।

केंद्र सरकार का रुख व याचिका

- 11 मार्च के फैसले के बाद, **केंद्र सरकार (DoPT)** ने सुप्रीम कोर्ट में एक **संशोधन/स्पष्टीकरण याचिका (Modification/Clarification Application)** दाखिल की।

सरकार का कहना है:

- **व्यापक नीतिगत प्रभाव (Policy Ramifications):** सरकार ने कहा कि फैसले के व्यापक नीतिगत और व्यावहारिक प्रभाव हो सकते हैं। इससे उच्च आय वाले (प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत) माता-पिता के बच्चे भी Non-Creamy Layer में शामिल हो सकते हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले वास्तविक जरूरतमंद OBC उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित होंगे।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- **CSE 2025 बैच और लॉजिस्टिक्स में समस्या:** UPSC Civil Services Examination (CSE) 2025 की चयन प्रक्रिया (958 अनुशंसित उम्मीदवार) पूरी हो चुकी है और सेवा आवंटन (Service Allocation) अंतिम दौर में है। फैसले को भूतलक्षी प्रभाव (Retrospectively) से लागू करने पर पूरा मेरिट लिस्ट बदलना पड़ेगा, जिससे IAS/IPS कैडर आवंटन, ट्रेनिंग शेड्यूल और नए बैच की वरिष्ठता (Seniority) प्रभावित होगी।

सरकार की मांग:

- सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस फैसले को **CSE-2025 और पुरानी पूरी हो चुकी भर्तियों/दाखिलों पर भूतलक्षी प्रभाव (Retrospectively) से लागू न किया जाए** (इसे Prospective Overruling के तहत देखा जाए)।
- सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वह निजी क्षेत्र और PSU कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर तय करने का एक **नया और एकसमान (Uniform) ढांचा/नीति** तैयार करेगी।

Q:- आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़े मुद्दों की चर्चा कीजिए और उदाहरण सहित समाधान भी सुझाइए। (250 शब्द)

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

महाराष्ट्र का महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2026 भारतीय संविधान के अनु० 21 और 25 का उल्लंघन करता है चर्चा कीजिए।

YouTube Homework

- Article 25-28

Civil society groups mount opposition to Maharashtra Freedom of Religion Act, demand to put law on hold

Yohaan Varghese
MUMBAI

The coalition said its main concerns included third-party complaints, reversal of the burden of proof, cognisable and non-bailable offences, and the broad definition of 'allurement'. YOHAAN VARGHESE

The Joint Civil Society, a coalition of civil society groups, women's outfits and religious bodies, has opposed the Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026, calling it a "serious threat to Constitutional freedoms, privacy and social harmony", days before the law is set to come into force on August 28.

In a statement issued on Monday, it said provisions requiring prior notice, declarations, reporting and police scrutiny of religious conversions could subject matters of faith, marriage and personal choice to intrusive state oversight.

The coalition has demanded that the implementation of the law be put on hold until the Supreme Court decided the challenge to similar enactments made by some other States.

The group also cited the recent invocation of the Act by the Pune police in two FIRs before the law was due to come into force. The police subsequently removed the provisions after the State government notified August 28 as the commencement date.

The Joint Civil Society said its main concerns included third party complaints, reversal of the burden of proof, cognisable and non-bailable offences, and the broad definition of "allurement", which it said could place legitimate charitable, educational and religious activities under scrutiny.

The coalition also argued that the Act disproportionately affects women, young adults, Dalits and Adivasis by restricting their autonomy in matters of faith and relationships. It said mandatory disclosures and police inquiries were difficult to reconcile with Constitutional protections of religious freedom, privacy, dignity and personal liberty.

Father Frazer Mascarenhas, former principal of St. Xavier's College, questioned whether free or affordable education and religious healing services could be construed as 'allurement' under the law. "How can education be considered inducement to convert?" he said, warning that the provisions could affect religious organisations as well as the communities they serve.

'Consenting adults'

Activist Sandhya Gokhale said the law undermined the autonomy of consenting adults, particularly women, in choosing their faith and relationships. "Earlier, the government had released a government resolution on inter-caste/inter-religion, and police would go to homes to check whether this was happening. They couldn't find anyone, and now they have this law," she said.

"They don't think of women as human or equal, but as objects. If we really want religious freedom, I think the child should have no religion when they are born, and once they reach the age of 18, they can decide for themselves what religion they want to accept. How can the government decide whose child belongs to which religion?" Ms. Gokhale added.

Advocates Irfan Engineer and Lara Jesani, author Tushar Gandhi, the great-grandson of Mahatma Gandhi, and Justice Abhay Thipsay, a former judge of the Bombay High Court, also expressed strong views against the law.

महाराष्ट्र सरकार
⇓
Maharashtra Freedom of Religion Act 2026

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- **महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026** (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) को मार्च 2026 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद **जुलाई-अगस्त 2026** में यह कानून पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र यह कानून बनाने वाला भारत का 13वां राज्य बन गया है।

1. अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

- **जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर रोक:** बल (Force), छल-कपट (Fraud), प्रलोभन/लालच (Allurement/Inducement) या विवाह का झूठा वादा करके कराए गए धर्मांतरण को गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- **सख्त सजा और जुर्माना:**
    - गैर-कानूनी धर्मांतरण के लिए **7 साल तक की जेल** और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।
    - यदि पीड़ित **नाबालिग, महिला, या SC/ST वर्ग** का व्यक्ति है, तो सजा **10 साल तक की जेल** और जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
    - बार-बार अपराध करने वाले (Repeat Offenders) के लिए 10 साल तक की सख्त कैद।
- **धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादियां रद्द:** यदि किसी विवाह का एकमात्र उद्देश्य गैर-कानूनी धर्मांतरण पाया जाता है, तो सक्षम अदालत द्वारा उस विवाह को **अमान्य (Null and Void)** घोषित कर दिया जाएगा।
- **बच्चों की सुरक्षा:** ऐसी शादियों से पैदा हुए बच्चों की धार्मिक पहचान, शादी से पहले माता के मूल धर्म के अनुसार मानी जाएगी।
- **पूर्व-सूचना देना अनिवार्य (60 दिन पहले):** यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे धर्मांतरण से कम से कम **60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को लिखित नोटिस** देना होगा।
- **गैर-जमानती अपराध:** इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) और **गैर-जमानती (Non-Bailable)** बनाए गए हैं।
- **तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत:** केवल पीड़ित ही नहीं, बल्कि पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार भी एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकते हैं।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

2. इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? (Why it is being Opposed)

- नागरिक अधिकार संगठनों (Civil Rights Groups), अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों (विशेषकर ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं) तथा विपक्षी दलों द्वारा इस कानून का कड़ा विरोध किया जा रहा है। विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का हनन:** आलोचकों का तर्क है कि 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देने और सत्यापन कराने की बाध्यता संविधान के **अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार)** और **अनुच्छेद 25 (धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता)** का उल्लंघन करती है।
- **कानून के दुरुपयोग की आशंका (Misuse by Vigilante Groups):** विरोध करने वालों का कहना है कि तीसरे पक्ष (रिश्तेदारों) को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देने से दक्षिणपंथी और असामाजिक तत्वों को अंतरधार्मिक जोड़ों (Interfaith Couples) और धार्मिक सभाओं को प्रताड़ित करने का औजार मिल जाएगा।
- **परोपकार और धर्मार्थ कार्यों पर प्रभाव:** ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक संस्थाओं का डर है कि उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा (Charity) के कार्यों को भी "प्रलोभन" (Inducement) या "ब्रेनवॉशिंग" मानकर एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
- **प्रार्थना सभाओं में सुरक्षा की चिंता:** मुंबई और आसपास के क्षेत्रों (MMR) में चर्च और प्रार्थना सभा आयोजकों ने विरोध और उत्पीड़न से बचने के लिए आने वाले लोगों से "स्वैच्छिक सहमति पत्र" (Self-Declaration Forms) भरवाना शुरू कर दिया है ताकि वे साबित कर सकें कि लोग अपनी मर्जी से प्रार्थना में आए हैं।
- **साबित करने का भार (Burden of Proof):** कानून के तहत धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डाला गया है कि धर्मांतरण जबरन नहीं हुआ है, जो कि आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत (साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व शिकायतकर्ता का होता है) के विपरीत है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

Wearing hijab not established as 'essential religious practice' for women in Islam, says HC

Ishita Mishra
NEW DELHI

The Allahabad High Court recently held that wearing a headscarf could not be established as an "essential religious practice" of Islam. The observation was made on a Muslim student's petition for permission to wear hijab along with her school uniform.

A Division Bench of Justices J.J. Munir and Indrajeet Shukla, in an order of August 21, dismissed the petition filed by a Class 11 student of Tagore Public School in Prayagraj.

In her plea, the student argued that wearing the scarf was an essential religious practice protected by her fundamental rights under Articles 14 and 19(1)(a) of the Constitution. She had previously worn a headscarf at the same school from Class 6 without objection, she said.

The court said the dispute was principally about compliance with institutional dress code.

The fact that the student had worn the scarf for several years did not create an enforceable right to compel the school to relax or alter its uniform policy, the High Court said.

"We have perused the photographs from various classes relating to the petitioner. Except for her, no other girl student is donning the headscarf, even those belonging to the same religious community as the petitioner. Wherever this issue has arisen, the High Courts have been unanimous in opinion that wearing a headscarf is not essential part of the Islamic faith, in the absence of which faith would be jeopardized," the court said.

No factual foundation had been laid nor material placed on record to establish that donning headscarf was an essential part of religion for a Muslim female, the High Court further said. The court relied on the judgments of the Bombay and Karnataka High Courts concerning hijab.

It held that the dispute was principally about compliance with an institutional dress code rather than interference with the student's freedom of faith.

"The school in this case does not seek to curtail the petitioner's freedom of faith at all. All that they require is conformity to institutional discipline, of which a uniform is an essential part," it said.

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब से जुड़े मामलों पर फैसले दिए हैं:

1. स्कूल/कॉलेज यूनिफॉर्म और क्लासरूम मामला

- **फैसला:** कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।
- **मुख्य बिंदु:** अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) को अपना ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। अनुशासन बनाए रखने के लिए तय की गई यूनिफॉर्म का पालन करना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

UN panel flags violations against SC, ST, Rohingya

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD) has said it is "gravely concerned" about reports of human rights violations against a vast segment of people in India, including Scheduled Tribes, Scheduled Castes, and Rohingya refugees.

In a press note that came on the ninth anniversary of the Rohingya crisis, the committee called for urgent action to address "hate speech" and "hate crime" in India. It said that there had been an increase in incidents targeting Bengali-speaking Muslims and called on the Government of India to "ensure accountability" for these violations.

"The committee was gravely concerned about reports of large-scale violations perpetrated by law enforcement officials against ethnic and ethno-religious groups, indigenous and tribal people, including Scheduled Tribes, Scheduled Castes, particularly Dalits, and non-citizens," it said.

The remarks came a fortnight after the committee carried out the eleventh periodic review of India on August 11-12. India had sent Solicitor-General Tushar Mehta as the head of delegation for the review.

The committee said these communities had been subjected to "racially motivated violence, excessive use of force, extrajudicial killings, arbitrary and prolonged detention without due process, torture, ill-treatment and sexual violence".

"The committee called on India to conduct prompt, thorough and impartial investigations into all such allegations and ensure accountability for those responsible," the press note said.

The panel further noted that there had been an increase in law enforcement operations targeting "Rohingya, Bengali-speaking Muslims, migrants and asylum-seekers, particularly following the 2017 Ministry of Home Affairs order and the April 2025 Pahalgam terror attack in Kashmir". The panel said that police check posts had resorted to racial profiling that led to "arbitrary arrest and detention without due process".

Minorities Rights 29/30

UNCERD

YouTube Homework

- UN

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- **UNCERD (United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination)** — यानी **नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति**, संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक प्रमुख मानवाधिकार संस्था है।
- यह संस्था मुख्य रूप से **CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)** संधि के कार्यान्वयन और निगरानी का काम करती है।

1. प्रमुख उद्देश्य (Objectives)

- **नस्लीय भेदभाव की समाप्ति:** दुनिया भर में जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या जातीय मूल (Race, Colour, Descent, National or Ethnic origin) के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना।
- **समानता को बढ़ावा:** यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों और नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता का बिना किसी भेदभाव के लाभ मिले।

2. संरचना और कार्यप्रणाली (Structure & Functions)

- **सदस्य:** इसमें **18 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ** शामिल होते हैं, जिन्हें सदस्य देशों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये विशेषज्ञ अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
- **समीक्षा रिपोर्ट (State Reports Review):** CERD संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि वे अपने देश में नस्लीय/जातीय भेदभाव रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। UNCERD इन रिपोर्टों की जांच करती है और सिफारिशें जारी करती है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Procedure):** यदि किसी देश में नस्लीय तनाव या बड़े पैमाने पर भेदभाव बढ़ने की आशंका होती है, तो यह समिति गंभीर स्थिति को रोकने के लिए चेतावनी जारी करती है।
- **अंतर-राज्यीय व व्यक्तिगत शिकायतें:** यह समिति राज्यों के बीच के विवादों और (कुछ शर्तों के तहत) व्यक्तिगत नागरिकों की भेदभाव संबंधी शिकायतों पर विचार कर सकती है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

3. भारत और UNCERD

- भारत ने **1968 में CERD संधि पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की थी।**
- समिति में भारत की ओर से ऐतिहासिक रूप से विभिन्न विशेषज्ञ सेवा दे चुके हैं।
- UNCERD की समीक्षा बैठकों में भारत की सामाजिक व्यवस्था, विशेष रूप से **जातिगत भेदभाव (Castes System), अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST)** और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा और सुझाव दिए जाते रहे हैं।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

- Recent Judgement Of SC

End the culture of secrecy in judicial appointments

Puhazh Gandhi P.

Lawyer and political analyst who writes on the Constitution, commerce and policies

The debate over transparency in judicial appointments has resurfaced after Justice Ujjal Bhuyan of the Supreme Court of India recently observed that greater openness in the collegium process would strengthen public confidence and help ensure that merit remains the governing principle. Reformers argue that insulation from political interference was never meant to become insulation from constitutional accountability itself – a question that has remained unresolved for three decades.

The collegium is a judicial creation, not a constitutional one. The First Judges Case (1981) gave the executive primacy in appointments; the Second Judges Case (1993 4 SCC 441) shifted primacy to the collectively formed opinion of the Chief Justice of India and senior judges; the Third Judges Case (1998 7 SCC 739) expanded this into today's five-member collegium. The reasoning was sound, but close to three decades later, the process remains among the least transparent in any major constitutional democracy: no notification of vacancies, no eligibility matrix, no known methodology for assessing candidates. Even Fali Nariman, credited as an architect of the collegium, later turned critic, recalling that it was 'not receptive at all' to the Bar. When the system's own architects concede that it answers to no one, reform can hardly be called interference.

Resolutions without reasons

One has the example of the collegium's own record on disclosure, which has moved backwards, not forwards – perhaps the clearest evidence of an institution retreating deeper into opacity. In October 2017, it began publishing resolutions with brief reasons for elevation, a step then hailed as a foundation for transparency.

That practice thinned steadily, and since November 28, 2024, resolutions have stopped naming which members took part in a decision or disclosing any reasoning at all. In November 2025, (then) Chief Justice of India (CJI) B.R. Gavai confirmed that the collegium had resolved to stop publishing detailed reasons altogether, citing concern that disclosure could harm the career prospects of candidates – a rationale that would equally justify withholding reasons from every rejected litigant.

This cannot be seen in isolation: the Court, in the MediaOne judgment (2023), held that sealed-cover secrecy is 'antithetical to a transparent and accountable system'. If that principle governs the court's own cases, why should a lesser standard govern its own?

This absence of due process has fuelled a recurring allegation: that opacity has allowed relatives of sitting and retired judges – the so-called 'Uncle Judges' – an easier passage to the Bench than first-generation lawyers with no lineage to lean on. It is important to remember this is not a complaint from critics from outside alone: former CJI R.M. Lodha himself remarked that nearly one in three High Court judges could be an 'uncle'.

The allegation is not anecdotal: in 2018, the Union government flagged 11 of the 33 names recommended by the Allahabad High Court collegium, noting that they were relatives of sitting or retired judges. A broader assessment in 2025 found that nearly 30% of the Supreme Court judges – roughly 10 of 33 – had familial links to former judges. In January 2025, this issue pushed the collegium to consider barring judges' kith and kin from consideration altogether (the proposal was discussed and in principle it was agreed to have higher scrutiny if candidates are relatives, but legally a bar was not created). That, in itself, is an admission that without a publicly defined selection matrix, there is no objective way to distinguish a meritorious relative from a beneficiary of judicial lineage.

This is where the judiciary's own jurisprudence turns inward. Articles 14 and 16 guarantee equality and equal opportunity in public employment. In *Secretary, State of Karnataka and Others vs Umadevi* (2006 4 SCC 1), the Court held that appointments to public office cannot be made through backdoor methods and must ordinarily follow a transparent procedure open to eligible candidates. If constitutional equality demands openness in the recruitment of a clerk or an engineer, why should the highest constitutional offices remain exempt from comparable standards? To be sure, judicial appointments cannot be reduced to a competitive examination; qualities such as independence and temperament resist quantification. But, qualitative judgment does not require the total absence of procedure. It is prudent to note the irony: the Court itself held, in *CPIO vs Subhash Chandra Agarwal* (2019 3 SCC 1), that the CJI's office falls within the Right to Information Act – a logic never extended to how judges are appointed.

> The judiciary that demands transparency from every institution of governance cannot ask citizens to trust it on faith alone

What other democracies do

Other constitutional democracies show that transparency and judicial independence can coexist. In the United Kingdom, the Judicial Appointments Commission publicly advertises vacancies and conducts structured interviews; in South Africa, the Judicial Service Commission invites nominations publicly and conducts televised interviews. None of these systems is flawless, but each rests on a premise that India has yet to accept: independence is strengthened, not weakened, when citizens understand how judges are chosen.

India's collegium continues to operate as though it belongs to an earlier era of institutional deference. Political theorist Jürgen Habermas argued that democratic legitimacy ultimately rests on the public sphere – an arena where institutions must justify themselves before informed citizens.

This is not abstract: every judicial appointment is now dissected on social media within minutes. The scrutiny of a CJI's own remark comparing youngsters to 'cockroaches' travelled from placards at Jantar Mantar to trending hashtags within hours; it will not take long for such movements to arrive at the doorstep of the higher judiciary itself. Contempt jurisdiction, built for the newsroom and the courtroom gallery, cannot be used to trifle the scrutiny of this scale and anonymity – it is an alarm bell for a system that still keeps its own appointments behind closed doors and resists constructive criticism. Institutions that embrace reform voluntarily emerge stronger; those that resist witness a slow erosion of the legitimacy they seek to protect.

Reform, not retreat

None of this requires dismantling the collegium; it only requires modernising it. A transparent framework could publish anticipated vacancies in advance, invite applications from eligible advocates, disclose objective eligibility criteria, and record reasoned recommendations explaining why one candidate was preferred over another. Confidential inputs on integrity can remain protected – transparency does not demand disclosure of every file, only openness about the process, the criteria and the reasoning behind constitutional appointments.

This is ultimately not a contest between the judiciary and the executive, nor an attempt to weaken judicial independence. It is a question of whether one constitutional value is allowed to eclipse another. The Constitution promises an independent judiciary, but, equally, promises equality, fairness and reasoned decision-making;values that are complementary, not adversarial. The debate of the 1990s was executive versus judiciary. The debate of this decade is opacity versus transparency. Therefore, unless the collegium accepts that independence without accountability breeds the very distrust it was designed to prevent, this asymmetry between what the judiciary demands of every other institution and what it permits of itself will continue to exist.

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

- South Asia
  - दक्षिण एशिया क्या है
  - समस्याएँ
  - समाधान

'Border stability is an immediate priority'

'Institutionalising stability' on the border is the immediate task for both countries rather than expecting a sudden 'dramatic settlement', says Chinese strategic affairs scholar Hu Shisheng; both sides have incentive for a favourable political atmosphere for possible leader-level interaction, he adds

Ananth Krishnan
BEIJING

As India and China on Tuesday held the 25th round of border talks between National Security Adviser Ajit Doval and China's Foreign Minister Wang Yi in Beijing, Hu Shisheng, a leading Chinese strategic affairs scholar on South Asia, said "institutionalising stability" is the immediate task for both countries even as "structural differences" in the relationship remained.

"On the border, I would expect the immediate focus to be less on a dramatic settlement and more on institutionalising stability. The priority is to prevent misunderstanding and miscalculation along the LAC, strengthen military and diplomatic communication, and turn last year's idea of an 'early harvest' into an operational process," Mr. Hu, who is Director of the South Asia Institute at the China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) in Beijing, told *The Hindu*.

He was referring to an agreement at last year's 24th round on establishing an Expert Group under the Working Mechanism for Consultation and Coordination (WMCC) on border affairs to explore "early harvest on boundary delimitation".

Mr. Hu said the timing of Mr. Doval's visit, before the September 12 BRICS Summit in New Delhi, added significance to the visit with Mr. Xi expected to visit India.

A satellite image taken in June 2020 shows the Line of Actual Control and Patrolling Point 14 in the eastern Ladakh sector. AFP

"Both sides have a strong incentive to keep the border stable and create a favourable political atmosphere for possible leader-level interaction," he said, adding that he viewed maintaining stability on the border, achieving "concrete and operational progress" on "early harvest" outcomes, and creating favourable conditions for the BRICS Summit as immediate priorities.

At the strategic level, he added, Mr. Doval's visit would help "clear potential obstacles ahead of the BRICS Summit and lay the groundwork for possible leader-level engagement."

He added that ensuring no unexpected border incident before the summit, setting the political tone and identifying deliverables for a possible leaders' meeting, and coordinating the handover of the BRICS agenda from India to China, which takes over as chair next year, would be three essential issues on the table.

Gradual normalisation

The view in Beijing, as in Delhi, is that the normalisation in relations since the October 2024 meeting between Mr. Modi and Mr. Xi is likely to remain gradual and measured.

"As for the broader normalisation, I would describe it as strategic risk management rather than strategic realignment," Mr. Hu said.

"Recent difficulties in India-U.S. relations may give New Delhi greater incentives to diversify its strategic options, while the relative stabilisation of China-U.S. ties reduces some of the external pressure on China-India relations. But the structural differences between China and India have not disappeared. What we are seeing is an attempt to build a more stable form of competitive coexistence – keeping the border peaceful, restoring practical cooperation, and expanding coordination through BRICS and the Global South without pretending that strategic competition no longer exists."

India-china

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

कूटनीतिक बातचीत (Special Representatives' Talks)

- सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजनीतिक व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है:
- **25वें दौर की वार्ता (25th SR Talks):** भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) **अजीत डोभाल** और चीन के विदेश मंत्री **वांग यी** के बीच अगस्त 2026 में बीजिंग में 25वें दौर की 'विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता' हुई।
- **भारत का रुख:** भारत ने साफ किया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति (Normalcy) तभी आ सकती है जब **सीमा पर शांति और स्थिरता (Peace & Tranquillity)** बनी रहे।
- **चीन का रुख:** चीन सीमा मुद्दे को प्राथमिकता देने के बजाय व्यापार और अन्य द्विपक्षीय संबंधों को अलग रखकर आगे बढ़ाना चाहता है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

- India-Myanmar

Rohingya refugees rally in Bangladesh camps demanding return to Myanmar

Associated Press
COX'S BAZAR

Exodus anniversary: Rohingya demonstrators gather during an event at a refugee camp in Cox's Bazar in Bangladesh. AP

Tens of thousands of Rohingya refugees from Myanmar living in dozens of camps in Bangladesh held a rally Tuesday to demand their safe return to their home state, nine years after they fled a government crackdown.

The demonstrators urged the international community to ensure security in Rakhine state as they marked what they call the "Ninth Anniversary of Rohingya Genocide Day".

More than one million refugees from Myanmar's Rohingya ethnic and religious minority now live in the sprawling camps around the Cox's Bazar district of southeastern Bangladesh.

Most of them fled across the border in a mass exodus in 2017 after Buddhist-majority Myanmar launched a crackdown in Rakhine, following an attack by a Rohingya Muslim insurgent group.

The Bangladesh government earlier attempted to start the repatriation at least twice, but it did not work out as none of the refugees was willing to go back, citing security concerns. Bangladesh says it will not force anyone to return.

In recent years, the security situation in Rakhine state has become more volatile.

"Whether it is the Arakan Army or the Myanmar military, as long as they continue playing this double game, the situation in Arakan, or Rakhine, will not become safe. Does that mean we are expected to remain here for another 50 years," Rohingya refugee leader Sayed Ullah said on Tuesday. Arakan is the old name of Rakhine.

Earlier, Myanmar's military-backed government said that more than 300,000 Rohingya refugees living in camps in Bangladesh are former residents of Rakhine state and that it will accept their return once security conditions improve.

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

- **रोहिंग्या (Rohingya)** म्यांमार (बर्मा) के रखाइन राज्य (Rakhine State) में रहने वाला एक मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। वे सदियों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार सरकार और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी उन्हें अपने देश का नागरिक मानने से इनकार करती रही है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने रोहिंग्या समुदाय को **"दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक"** करार दिया है।

1. संकट की मुख्य वजहें (Core Conflict)

- **नागरिकता का अभाव (1982 का कानून):** म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्याओं को देश के 135 आधिकारिक जातीय समूहों में शामिल नहीं किया गया। उन्हें "अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी" माना गया, जिससे वे राज्यविहीन (Stateless) हो गए।
- **अधिकारों से वंचित:** नागरिकता न होने के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और स्वतंत्र आवाजाही के बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
- **2017 का सैन्य अभियान (Mass Exodus):** अगस्त 2017 में रखाइन राज्य में रोहिंग्या विद्रोहियों द्वारा पुलिस चौकियों पर हमले के बाद म्यांमार सेना ने भारी सैन्य कार्रवाई की। इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और हत्याओं की घटनाएं हुईं। इसके परिणामस्वरूप **7 लाख से अधिक रोहिंग्या** अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने पर मजबूर हुए।

2. वर्तमान स्थिति (Present Status)

- **बांग्लादेश में शरणार्थी:** बांग्लादेश के **कॉक्स बाज़ार (Cox's Bazar)** और **भाषण चार (Bhasan Char)** द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर स्थित है, जहाँ लगभग 10 लाख से अधिक रोहिंग्या बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मामला:** म्यांमार की सेना और सरकार पर रोहिंग्याओं के खिलाफ **नरसंहार (Genocide)** के आरोप लगे हैं। गाम्बिया द्वारा दायर याचिका पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
- **म्यांमार का गृहयुद्ध:** 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों (जैसे अराकान आर्मी) के बीच जारी गृहयुद्ध के कारण रखाइन राज्य में बचे हुए रोहिंग्याओं की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है।

3. भारत का रुख (India's Position)

- **शरणार्थी स्थिति:** भारत में अनुमानित 40,000 से अधिक रोहिंग्या रहते हैं (जिनमें से कई UNHCR कार्डधारक हैं)। भारत 1951 के UN शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** भारत सरकार रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी मानती है और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से उन्हें "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा" मानती है।
- **मानवीय सहायता और वापसी:** भारत बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत राहत सामग्री भेजता रहा है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य में विकास कार्य करके ऐसी परिस्थितियां बनाना है ताकि रोहिंग्या सुरक्षित रूप से अपने मूल देश वापस लौट सकें।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

Iran, Oman discuss temporary Hormuz path, mine-clearing

Agence France-Presse
MUSCAT

Iran and Oman's Foreign Ministers on Tuesday said they discussed a framework for a temporary transit corridor through the Strait of Hormuz and a mine-clearing project in the waterway, which they both border.

Omani Foreign Minister Badr Albusaidi and his Iranian counterpart Abbas Araghchi "discussed a phased framework that could provide a practical and implementable basis for moving forward" during talks in Tehran, a joint statement shared by Oman said.

The framework "includes the establishment of a joint temporary navigational corridor through the Strait of Hormuz and an agreement to implement a joint project to clear the Strait of mines", the statement added.

Mr. Albusaidi said in a post on X after the meeting that he hoped the countries would "soon announce" the temporary corridor in the strait.

The announcement came as U.S. President Donald Trump repeated claims on Truth Social that "all mines have been removed and/or detonated from within the International Waters of the Strait of Hormuz", citing the U.S. navy.

Iran-Oman
Hormuz

YouTube Homework

- USA-IRAN War

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री कार्यालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधानमंत्री ने यूपीआई के एक दशक पूरे होने पर नागरिकों को अपने यूपीआई अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया

प्रविष्टि तिथि: 25 AUG 2026 11:12AM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की परिवर्तनकारी यात्रा को स्मरण किया, जिसका शुभारंभ एक दशक पहले हुआ था। यूपीआई ने भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए देश में त्वरित, सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल लेन-देन को नई गति प्रदान की।

पिछले दस वर्षों में यूपीआई ने देश के कोने-कोने तक अपनी व्यापक पहुंच बनाते हुए डिजिटल भुगतान को आम नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूपीआई की इस उल्लेखनीय और गौरवपूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी उपलब्धियों पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने यूपीआई उपयोग के अनुभव साझा करने और यह बताने का भी आग्रह किया कि यूपीआई ने उनके दैनिक जीवन को किस प्रकार सरल, सुविधाजनक और सहज बनाया है।

- **UPI (Unified Payments Interface)** की शुरुआत आधिकारिक तौर पर **11 अप्रैल 2016** को हुई थी।
- इसे **NPCI (National Payments Corporation of India)** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे 21 सदस्य बैंकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, और **25 अगस्त 2016** से इसे आम जनता के लिए पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया था। — 10 वर्ष

YouTube Homework

- **NPCI** ??
  - UPI ??

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

खान मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 'क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026' लॉन्च किया

छात्रों, शोधकर्ताओं, आरएंडडी संस्थानों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अहम खनिजों की खोज और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है

प्रविष्टि तिथि: 25 AUG 2026 5:49PM by PIB Delhi

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' के लक्ष्यों को मजबूती देने के उद्देश्य से आज 'क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हेकाथॉन 2026' (सीएमआईएच 2026) लॉन्च किया। इसके तहत छात्रों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक और आरएंडडी संस्थानों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अहम खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़ी चुनौतियों के लिए नए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह हेकाथॉन प्रतिभागियों को अपने आइडिया दिखाने, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन पाने और भारत में जरूरी खनिजों के लिए एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने में योगदान देने का प्लेटफॉर्म देता है। यह दो मुख्य समस्याओं पर फोकस करता है: ओपन डेटा से मिनरल प्रोस्पेक्टिविटी मैपिंग, जिसमें लिथियम या आरईई पेग्मेटाइट्स के लिए प्रोस्पेक्टिविटी हीटमैप बनाना और ज्ञात खनिज स्थलों से उसे सत्यापित करना शामिल है और अहम खनिजों के लिए स्मार्ट तकनीक और पेटेंट ट्रैकर, जिसका उद्देश्य जरूरी खनिजों के लिए एक आसान, वेब-बेस्ड स्मार्ट आरएंडडी और पेटेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

Azadi Ka Amrit Mahotsav

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने आईआईटी मद्रास में पहले केमोकनेक्ट 2026 का आयोजन किया

आईआईटी मद्रास में जैविक रूप से अपघटित पैकेजिंग सामग्री (बायोपैक) पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन

प्रविष्टि तिथि: 25 AUG 2026 6:25PM by PIB Delhi

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने आज ,25 अगस्त 2026को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)आईआईटी (मद्रास में पहले केमोकनेक्ट 2026का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में उद्योग जगत ,शिक्षा जगत ,स्टार्ट- अप और अनुसंधान संस्थानों के 200से ज़्यादा अग्रणी व्यक्तिओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों ने भाग लिया ,जिनमें विभाग द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

Result Mitra

महत्वपूर्ण तथ्य

गृह मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आसूचना ब्यूरो के 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित किया

मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, और विकसित भारत की पहली शर्त है मज़बूत आंतरिक सुरक्षा, हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनना है तो आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ करनी ही पड़ेगी

पहले की सरकारों ने नारकोटिक्स, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को विकराल होने से पहले ही विज़ुअलाइज़ किया होता तो देश को दशकों तक इनका दंश न झेलना पड़ता

आंतरिक सुरक्षा के तीनों हॉटस्पॉट में खड़ी चुनौती को हमने समाप्त किया है, इसका संपूर्ण यश हर राज्य की पुलिस फोर्स, केंद्रीय एजेंसियों और CAPF को जाता है

NSSC का यह फोरम आने वाले 15-20 सालों के ट्रेंड्स देखकर तय करे कि कौन-सी समस्या उठ सकती है और उसे रोकने की स्ट्रैटेजी क्या हो

पिछले आठ माह में सभी भूमि-सीमा राज्यों का दौरा कर हमने एक चतुष्कोणीय सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण का डॉक्यूमेंट राज्यों से साझा किया; बहुत कम समय में देश को घुसपैठिया मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है

NSSC 2026

New Delhi

अमितशाह IB

Result Mitra

Overview

- NADCP
- OBC Reservation
- Maharashtra Freedom of Religion Act 2026
- School Education & Hijab
- UNCERD
- SC & Collegium
- India-China Border Issues
- Rohingya Refugees
- Iran-Oman on Hormuz
- UPI
- Critical Mineral Innovation Hackathon
- First Chemconnect
- NSSC

Thank You

Result Mitra

ResultMitra